



-1-

समक्ष माननीय राजस्व मंडल मोप्र० गवालियर

निगरानी कमाक

/2016 जवलपुर

फैग - ३७२३ - I - ६

सुरेश कुमार धुर्व पिता छोटेलाल धुर्व निवासी ग्राम

मुकनवारा थाना बरगी तहसील व जिला जवलपुर

म.प्र. ।

आवेदक

विरुद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर
2. अनुचित पिता श्री आनंद जैन निवासी 302/बी, तिलखारा रोड, शास्त्री नगर चौक के पास गढ़ा तहसील व जिला जवलपुर म.प्र.

अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क 124/अ-21/2015-2016 मे पारित आदेश दिनांक 26.09.2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू - राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन निगरानी

माननीय महोदय,

सेवा मे आवेदक की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपवन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम मुकनवारा प0ह0न0 33 रानि.मं. बरगी तहसील व जिला जवलपुर मे स्थिति भूमि खसरा नं. 238/2, 238/3, 245/2, 245/3 रकवा कपाश 1.310 है। भूमि आवेदक की रवयं की निजी

[Signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुबृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3723/1/2016

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश
9.12.2016	<p>यह निगरानी कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 124/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26-09-2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू- राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने कलेक्टर जवलपुर को आवेदन पत्र देकर अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम मुकनवारा प.ह.न. 33 रानिमंबरगी, तहसील ब ज़िला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 238/2,238/3,245/2,245/3 रक्ता 1.310हेंड लबड़—खाबड़ होने एवं अन—उपजाउ होने से भूमि को विक्रय कर रख रही भूमि की उन्नती हेतु भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति मांगी। कलेक्टर जवलपुर प्रकरण क 124/अ-21/2015-16 पंजीबद्ध किया जाकर जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जवलपुर को भेजा गया अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच उपरांत प्रकरण क 72/अ-21/15-16 दर्ज कर विधिवत जांच की गई एवं जांच प्रतिवेदन हेतु नायव तहसीलदार वर्गी से जांच कराई जाकर कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर ली गई परन्तु उसके उपरांत भी कलेक्टर महोदय द्वारा विक्रय की अनुमति प्रदान न ही जाकर प्रकरण लिखित रखा गया है। जिससे दुरिक्षित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3— निगरानी मेसो में दर्शाए बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p>

(M)

SPB

4— आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध
अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि आवेदक ने उसके निजी स्वामित्व
की भूमि सर्वे कमाक 238 / 2,238 / 3,245 / 2,245 / 3 रकवा 1.310 हे. के विकास
की अनुमति इस आधार पर मांगी है कि यह भूमि पड़ती कम उपजाऊ और कुछ
हेतु अनुपयुक्त एवं पथरीली होने से विकास करना चाहता है। एवं ग्राम वाढ़ीवारा
एवं करेली की भूमि को सिचित एवं उपजाऊ करने हेतु विकास करना चाहता है।
उसके पास विकास की जाने वाली भूमि के अंतिरिक्त ग्राम वाढ़ीवारा रकवा 3.34
हे। एवं ग्राम करेली की की भूमि रकवा 4.49 भूमि शेष बच रही है। जिसके
कारण विकास की जाने वाली भूमि के विकास उपरांत वह भूमिहीन नहीं होगा एवं
भूमि विकास से प्राप्त धन से बच रही भूमि को उन्नत बनायेगा इसलिये भूमि
विकास का प्रयोजन भी सदभावना पर आघारित है जिसके कारण विकास अनुमति
दिये जाने में बैधानिक अडचन नजर नहीं आती है। वैसे भी आवेदक द्वारा
विकास की जा रही भूमि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है आवेदक द्वारा
संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के कारण भूमि विकास की अनुमति मांगी गई
है, एवं पटवारी हल्का नंबर ३३राठनि०मं० बरगी द्वारा भी अपने प्रतिवेदन में भूमि
विकास सदभावना पर माना है। एवं नाराव तहसीलदार बरगी द्वारा प्रस्तुत जांच
रिपोर्ट तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से प्रकरण की
परिस्थितियों के अनुसार भूमि विकास की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की
बैधानिक अडचन नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के रामक्ष अनुविभागीय अधिकारी
की जांच प्रतिवेदन होने के उपरांत भी पुनः जांच प्रतिवेदन मंगा कर प्रकरण को
लम्बित रखना चाहता है जो उचित एवं न्याय संगत नहीं है।

(1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादा विरुद्ध म०प्र०राज्य तथा एक
अन्य 2013 राठनि०-०८-माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टात है कि—

(1)भू-राजस्व संहिता , 1959 (म०प्र०)-धारा 165(7-ख)तथा 158 (3) का लागू
होना —उपबंधो के अंतःस्थापन से पूर्व पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान
किये गये —बिना अनुमति के भूमि का अंतरण—उपबंधो को भूतलक्षी प्रभाव नहीं
दिया गया—उपबंधो को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया—उपबंध आकर्षित नहीं

प्र॒

०८

होते—भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

(2)विधि का निर्वचन—का सिद्धात् —नवीन उपबंध का अंतःस्थापन —भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया —ऐसे उपबंधकी भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।

(2)दयाली तथा एक अन्य विरुद्ध महिला श्यामबाई 2004रा०नि०183में व्यवस्था की गई है कि भू—राजस्व संहिता 1959(म०प्र०)—धारा 165(7—ख) सरकारी पटटेदार द्वारा आबंटन के 10 वर्ष पश्चात् भूमिस्वामी अधिकार अंजित किये —भूमि का विक्य कर सकता है — कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नहीं है।

5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क 124 / अ—21 / 2015—16 अपील मे पारित आदेश दिनांक 26.09.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदक को ग्रम मुकनवारा प.ह.नं. 33 रा.नि.मं.बरगी , तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 238 / 2,238 / 3,245 / 2,245 / 3 कुल रकवा 1.310हौ० है० के विक्य की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:—

1—भूमि का क्य—विक्य के दस्तावेज का पंजीयन इस आदेश के चार माह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है।

2—भूमि का क्य—विक्य पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाईड लाईन के मान से किया जावेगा ।

3—केता द्वारा विक्य प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।


संकेत

प्रश्न